

## खनजि अधिकारों पर राज्यों द्वारा करारोपण शक्त को स्वीकृति

### प्रलमिस के लिये:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), संघ सूची, रॉयल्टी और कर, [महत्त्वपूर्ण खनजि](#), [प्रत्यक्ष वदिशी नविश](#), [शुद्ध-शून्य उत्सर्जन](#)

### मेन्स के लिये:

खनन क्षेत्र, भारत के खनन क्षेत्र का महत्त्व, शासन और नीति, औद्योगिक विकास

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने खनजि अधिकारों पर करारोपण से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए अपने वर्ष 1989 के नरिणय को खारजि कर दिया है तथा इस [संदर्भ में राज्य की शक्त की पुनः पुष्टि की है](#)।

- नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गए इस नरिणय से यह स्पष्ट हो गया है कि खनजि रॉयल्टी पर संसद और राज्यों के पास कतिना अधिकार है।

### सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नरिणय दिया?

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया कि [खान और खनजि \(विकास और वनियमन\) अधिनियम, 1957](#) तथा [संघ सूची की प्रवर्षि 54](#) के तहत [खनन वनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है](#)।
    - राज्यों को केवल [रॉयल्टी वसूलने](#) की अनुमति थी और अतिरिक्त करारोपण की अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत किया और उन पर कोई भी उपकर [राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर था](#)।
  - वर्ष 2004 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 1989 के एक नरिणय में मुद्दे संबंधी त्रुटि का सुझाव दिया था, जिसमें [संकेत दिया गया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है](#)। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस नरिणय की समीक्षा की।
- **वर्ष 1989 के नरिणय को खारजि किया:** सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया कि वर्ष 1989 का वह नरिणय गलत था, जिसमें [खनजि पर रॉयल्टी को MMDRA, 1957 के तहत कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था](#)।
- **राज्य बनाम केंद्रीय प्राधिकरण:** न्यायालय ने इस तर्क पर जोर दिया कि खनजि अधिकारों पर करारोपण शक्ति पूरी तरह से राज्यों के पास है, जबकि संसद केवल खनजि विकास में बाधाओं को रोकने के लिये सीमाएँ लगा सकती है।
  - इस नरिणय में स्पष्ट किया गया है कि [संसद को संविधान की सूची II की प्रवर्षि 50 के अंतर्गत खनजि अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है](#), जो [राज्य की शक्तियों](#) को नरिणय करती है तथा यह कर नहीं, बल्कि प्रतिबंध लगाने तक सीमित है।
  - संसद राज्यों के खनजि अधिकारों पर करारोपण के तरीके पर प्रतिबंध लगा सकती है, [लेकिन वह सीधे कर नहीं लगा सकती](#)। ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनजि विकास में बाधा न आए।
- **असहमतपूर्ण राय:** चेतावनी दी गई कि राज्यों को खनजि अधिकारों पर करारोपण की अनुमति देने से [सूची II की प्रवर्षि 49 के अंतर्गत भूमि और भवनों पर भी करारोपण का प्रयास किया जा सकता है](#), जिससे [संघीय प्रणाली](#) ध्वस्त हो जाएगी तथा खनजि मूल्य नरिधारण एवं विकास में [एकरूपता समाप्त हो जाएगी](#)।
  - परिणामस्वरूप राज्य पुनः [खनजि पर करारोपण शुरू कर देंगे](#), जिससे कानूनी अनश्चितता उत्पन्न होगी तथा भारत में धातु विकास सहित अन्य प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे।
  - खनजि मूल्य नरिधारण और विकास हितों में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा राज्यों को खनजि अधिकारों पर करारोपण से रोकने के लिये [संसद को हस्तक्षेप करना होगा](#)।

### रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है?

- वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'रॉयल्टी' और 'कर' के बीच अंतर को रेखांकित किया था।
- **रॉयल्टी:** यह पार्टियों के बीच एक समझौते से उत्पन्न होती है। यह अनुदानकर्त्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और वशिषाधिकारों के लिये भुगतान किया गया मुआवजा है।
  - रॉयल्टी भुगतान का अनुदान प्राप्तकर्त्ता को दिये गए लाभ या वशिषाधिकार के साथ सीधा संबंध होता है।
  - यह समझौते के लिये वशिषिट होता है और अक्सर संसाधनों के दोहन या अनुदानकर्त्ता द्वारा दिये गए वशिषाधिकार के उपयोग से जुड़ा होता है।
  - उदाहरण: न्यायालय ने हगिरि-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1961), पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) और अन्य सहित कई मामलों का संदर्भ देते हुए यह स्थापित किया कि रॉयल्टी प्रत्यक्ष लाभ के साथ संबद्धात्मक दायित्व है।
- **कर:** यह करदाता को दिये गए किसी वशिष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्त के तहत लगाया जाता है। इसे कानून द्वारा लागू किया जाता है और इसके लिये करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
  - कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये लगाए जाते हैं, लेकिन करदाता को कोई वशिष लाभ नहीं होता। ये सभी नागरिकों द्वारा वहन किये जाने वाले सामान्य बोझ का हिस्सा हैं।
  - रॉयल्टी के विपरीत करों में कोई लेन-देन व्यवस्था शामिल नहीं होती है। भुगतान अनिवार्य है और यह किसी वशिषाधिकार या लाभ से जुड़ा नहीं है।
  - उदाहरण: न्यायालय ने करों की वशिषताओं को उजागर करने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005) और जदिल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) सहित कई मामलों का उल्लेख किया।

## खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957 क्या है?

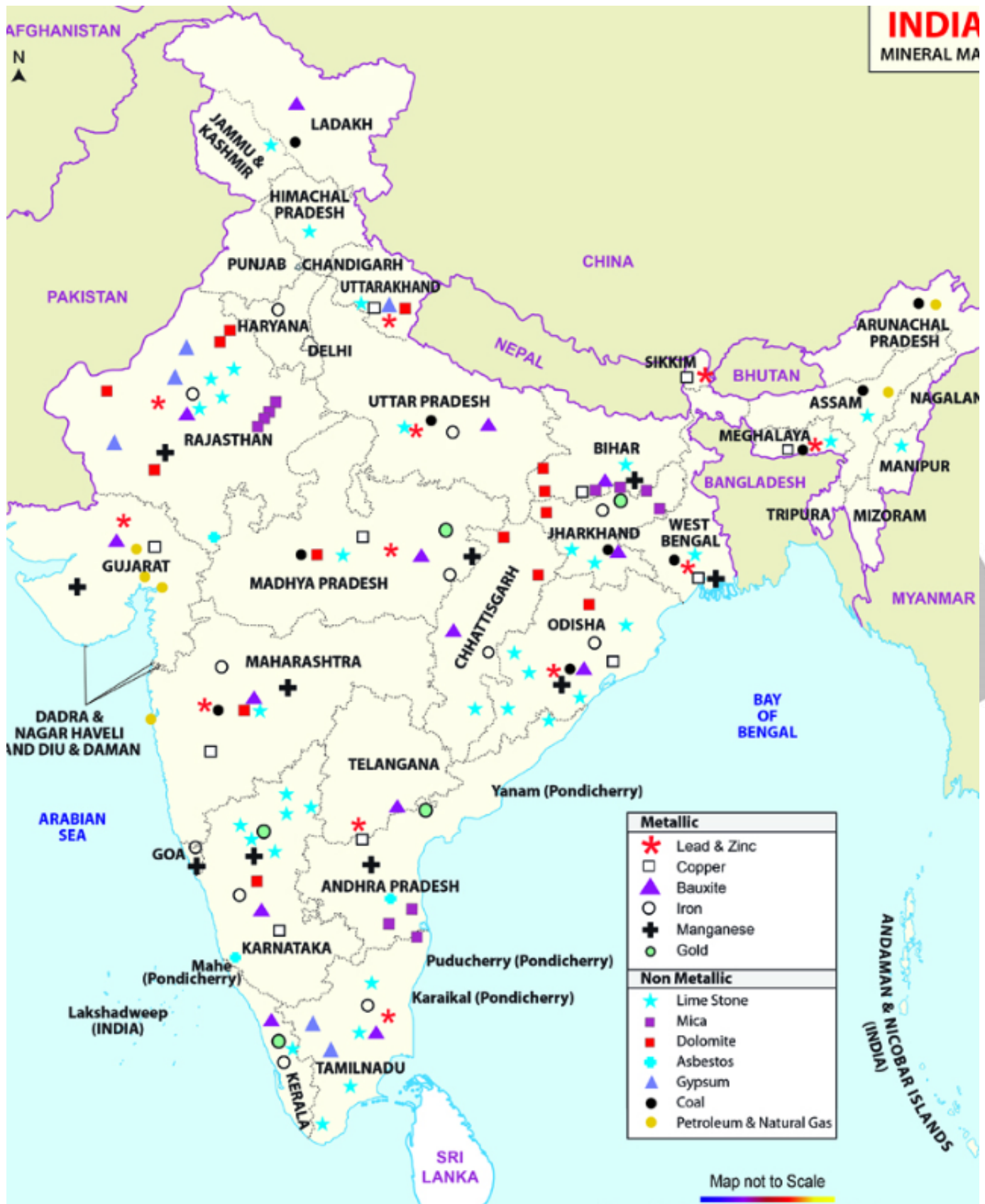
- यह भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। खनजि क्षेत्र में उभरती ज़रूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के लिये इस अधिनियम में कई संशोधन किये गए हैं, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के साथ इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- प्राथमिक उद्देश्य खनन उद्योग का विकास करना, खनजि संरक्षण सुनिश्चित करना तथा खनजि दोहन में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
- **2015 का संशोधन:** इस व्यापक संशोधन ने कई प्रमुख सुधार प्रस्तुत किये।
  - **नीलामी पद्धति:** आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये खनजि रियायतों की अनिवार्य नीलामी।
  - **ज़िला खनजि फ़ाउंडेशन (DMF):** खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये DMF की स्थापना की गई।
  - **राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET):** खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NMET की स्थापना की गई।
  - **अवैध खनन के लिये दंड:** अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कड़े दंड लागू किये गए।
- **वर्ष 2016 और 2020 संशोधन:** इस क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये छोटे-छोटे मुद्दों का समाधान किया गया।
- **2021 संशोधन:**
  - **कैप्टिव और मर्चेन्ट खदानों के बीच का अंतर हटा दिया गया।**
    - कैप्टिव खदानों का संचालन कंपनियों द्वारा वशिष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये खनजिों का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। कैप्टिव खदानों से निकाले गए खनजि, अंतिम उपयोग संयंत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनजि उत्पादन का 50% तक खुले बाज़ार में बेच सकते हैं, जिसके लिये सरकार द्वारा मूल रूप से खनजि ब्लॉक आवंटित किया गया था।
    - मर्चेन्ट खदानों का संचालन खुले बाज़ार में बिक्री के लिये खनजिों का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। निकाले गए खनजिों को विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है, जिनमें वे उद्योग भी शामिल हैं जिनके पास अपनी खदानें नहीं हैं।
  - **केवल नीलामी रियायतें:** यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नज्जि क्षेत्र की खनजि रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाएँ।
- **वर्ष 2023 का संशोधन:**
  - खान और खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण खनजिों की खोज और नषिकर्षण को मज़बूत करना है।
  - मुख्य संशोधनों में राज्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण तक सीमिति 12 परमाणु खनजिों की सूची से 6 खनजिों को हटाना, सरकार को महत्वपूर्ण खनजिों के लिये वशिष रूप से खनजि रियायतों की नीलामी करने का अधिकार देना शामिल है।
  - वदिशी प्रत्यक्ष नविश को आकर्षित करने और खनन कंपनियों को गहरे एवं महत्वपूर्ण खनजिों की खोज में शामिल करने के लिये अन्वेषण लाइसेंस दिये गए।
    - इन महत्वपूर्ण खनजिों की खोज और खनन में तेज़ी लाने के लिये आयात पर निर्भरता कम करने एवं नज्जि क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिये लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनजिों के महत्व को मान्यता दी गई एवं वर्ष 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन व शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया गया।

## भारत में खनन क्षेत्र का परिदृश्य

- **भारत के इस्पात क्षेत्र ने** उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे यह विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 144.04 मिलियन टन, तैयार इस्पात उत्पादन 138.83 मिलियन टन एवं तैयार इस्पात की खपत 136.65 मिलियन टन थी।
  - पिछले वर्ष की तुलना में तैयार इस्पात उत्पादन में 12.68% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि खपत में 13.9% की वृद्धि हुई।
- भारत के पास कुल कोयला भंडार 344.02 बिलियन टन है और यह विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - कोयला क्षेत्र में, जून 2024 के दौरान उत्पादन 84.63 मिलियन टन था, जो जून 2023 की तुलना में 14.49% की वृद्धि दर्शाता है।

- पछिले वर्ष की तुलना में संचयी कोयला उत्पादन में **11.65% की वृद्धि** हुई।
- **मैंगनीज़ और (इंडिया) लमिटिड ने वित्त वर्ष 2023-24 में 17.56 लाख टन मैंगनीज़ अयस्क का उच्चतम उत्पादन** हासिल किया, जो पछिले वर्ष की तुलना में **35% की वृद्धि** दर्शाता है। भारत के खनजि उत्पादन में भी अप्रैल-फरवरी, 2023-24 की अवधि के लिये 8.2% की संचयी वृद्धि देखी गई। देश की FDI नीति स्टील और खनन क्षेत्रों के साथ-साथ कोयला एवं लगिनाइट के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देती है।
- सत्र **2021-22 के लिये खनजि उत्पादन सूचकांक** (आधार सत्र 2011-12) **113.3** है, जो सत्र 2020-21 की तुलना में 12.17% की वृद्धि दर्शाता है।
  - सत्र 2021-22 के लिये खनजि उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनजिों को छोड़कर) का कुल मूल्य लगभग 220000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें धातु खनजिों का योगदान लगभग 120000 करोड़ रुपए है।
- **भारतीय खनन उद्योग** में बड़ी संख्या में छोटी परचालित खदानें हैं। सत्र 2021-22 में भारत में खनजि उत्पादन (लघु खनजिों, ईंधन खनजिों और परमाणु खनजिों को छोड़कर) की रपौट करने वाली खदानों की संख्या 1319 थी, जिनमें सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (263) में स्थित थी, इसके बाद गुजरात (147), कर्नाटक (132), ओडिशा (128), छत्तीसगढ़ (114), आंध्र प्रदेश (108), राजस्थान (90), तमिलनाडु (88), महाराष्ट्र (73), झारखंड (45) और तेलंगाना (39) थे।
  - सत्र 2021-22 में इन **11 राज्यों की देश में कुल खदानों की संख्या में 93% हस्तिसेदारी** थी।





2222222 222222 2222222:

प्रश्न. खनजि अधिकारों और रॉयल्टी के संबंध में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वभाजन का परीक्षण कीजयि जैसा क सिरवोच्च न्यायालय के नरिणय द्वारा स्पष्ट कयि गयि है ।

और पढ़ें...



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**प्रश्न:**

प्रश्न. भारत में गौण खनजि के प्रबंधन के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. इस देश में वदियमान वधिके अनुसार रेत एक 'गौण खनजि' है ।
2. गौण खनजिों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्ज सरकारों के पास है, कनितु गौण खनजिों को प्रदान करने से संबंधित नयिमों को बनाने के बारे में शक्तियों केंद्र सरकार के पास हैं ।
3. गौण खनजिों के अवैध खनन को रोकने के लयि नयिम बनाने की शक्ति राज्ज सरकारों के पास है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में 'ज़िला खनजि प्रतष्ठितान (डिस्ट्रिक्ट मनिरल फाउंडेशन्स)' का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

1. खनजि-सम्पन्न ज़िलों में खनजि-खोज संबंधी क्रयिकलापों को प्रोत्साहति करना
2. खनजि-कार्य से प्रभावित लोगों के हतियों की रक्षा करना
3. राज्ज सरकारों को खनजि-खोज के लयि लाइसेंस नरिगत करने के लयि अधिकृत करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**प्रश्न:**

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतशित का योगदान देते हैं। वविचना कीजयि। (2021)